

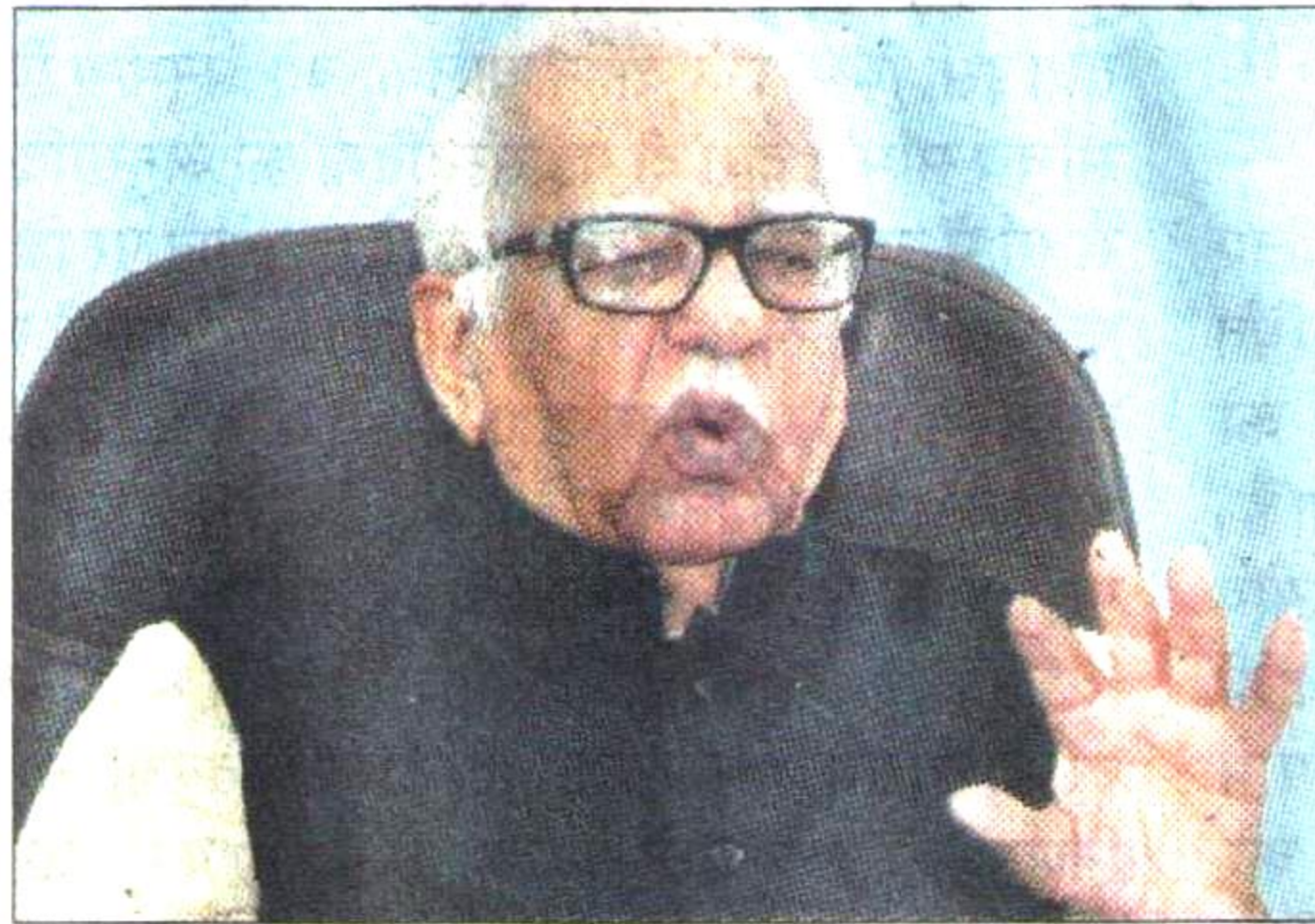
न बहुत मीठे साबित हुए न बहुत तीखे

अनिल सिंह

लखनऊ। राज्यपाल राम नाईक को यूपी में कार्यभार संभाले आज एक साल पूरा हो गया। इन एक सालों में राजभवन आम लोगों की चहलकदमी और आयोजनों से इतना गुलजार रहा, जितना पिछले एक दशक में देखने को नहीं मिला था। राम नाईक ने अपने पूर्ववर्ती कार्यवाहक राज्यपाल की तरह जनता दरबार तो नहीं लगाया, लेकिन सरकार के साथ लव-हेट वाले रिश्ते के बावजूद उनकी मंज़ी सियासत का ही कमाल रहा कि एक-दो मौकों को छोड़कर उंगलियां राजभवन की तरफ नहीं उठीं।

राम नाईक ने जब पिछले साल 22 जुलाई को यूपी के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभाली तो मोहनलालगंज के वीभत्स रेप व हत्याकांड से पूरी यूपी दहली हुई थी। यहीं से राज्यपाल ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने शुरू किए। कुछ नेताओं ने राज्यपाल पद की गरिमा को लेकर नाईक पर सवाल भी उठाए, लेकिन वे बिना विचलित हुए अपने काम में लगे रहे। सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन में भी राज्यपाल पर एक दल के प्रतिनिधि के रूप में काम करने के आरोप

जड़े गए। प्रदेश के कद्दावर मंत्री आजम खां ने भी राज्यपाल पर निशाना साधा, लेकिन राज्यपाल ने किसी भी मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। मंझे राजनेताओं की तरह



राज्यपाल ने मुलायम सिंह यादव से अपने

● विश्वविद्यालयों की दशा-दिशा सुधारने का किया प्रयास

संबंधों के बल पर उन्हें राजभवन में बुलाकर मुलाकात की तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अच्छी सोच वाला सीएम बताकर प्रशंसा भी की, लेकिन इसके बावजूद और बेहतर काम करने की बातें करके राज्य सरकार पर दबाव भी बनाए रखा। दरअसल, राज्यपाल ने अपनी छवि ऐसी गढ़ी कि न तो वे बहुत

मीठे लगे न बहुत तीखे। मुलायम और अखिलेश से अपने संबंध सहज रखे तो दूसरी तरफ आजम खां की इच्छा के विपरीत अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव को लौटाकर उस पर सवाल पूछा। गौतमबुद्धनगर विश्वविद्यालय के प्रस्ताव की तात्कालिकता के संदर्भ में सवाल भी दागा। एमएलसी मनोनयन प्रकरण में उन्होंने बनी बनाई परिपाटी छोड़कर संविधान का सहारा लिया तो पूरी सरकार को असहज कर दिया। जांच-पड़ताल के बाद राज्यपाल ने चार नामों को हरी झंडी दिखाई।

एमएलसी के पांच पद अब भी खाली पड़े हुए हैं। राज्यपाल ने सियासत से इतर इन एक सालों में राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था को भी पटरी लाने की कोशिश की। विश्वविद्यालयों में लंबे समय से बंद पड़े दीक्षांत समारोहों को शुरू कराया तो दूसरी तरफ सत्र संचालन समय से कराने के प्रयास भी किए। यानी एक साल में सियासत के अनुभव का पूरा प्रयोग राम नाईक ने राजभवन की चहारदीवारी के भीतर किया। संभावना है कि यह प्रयोग आगे भी जारी रहेंगे?